Akshardhara Research Journal
Single Blind Peer-Reviewed & Refereed International Research Journal
E ISSN -3048-8095 / Bimonthly / SJIF Impact- 5.16/ March - April 2026 / VOL-02 ISSUE-V

02

रायगढ़ जिले के लघु उद्योगों में रोजगार सृजन की संभावनाएँ और समस्याएँ

डॉ. विनोद एक्का
सहायक प्राध्यापक,
संत शिरोमणि गुरु रविदास शासकीय महाविद्यालय सरगांव जिला मुंगेली (छ.ग.)

सारांश– रायगढ़ जिला, छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख औद्योगिक एवं खनिज संपन्न क्षेत्र है, जहाँ लघु उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। यहाँ के प्राकृतिक संसाधन, कृषि आधारित उत्पादन, वन संपदा तथा स्थानीय कारीगरों की पारंपरिक दक्षता लघु उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। लघु उद्योग न केवल आर्थिक विकास को गति देते हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन का एक प्रभावी माध्यम भी हैं। विशेष रूप से ग्रामीण एवं अर्ध–शहरी क्षेत्रों में ये उद्योग स्वरोजगार और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराते हैं, जिससे बेरोजगारी में कमी आती है। रायगढ़ जिले में चावल मिल, लोहा–इस्पात आधारित छोटे उद्योग, हस्तशिल्प, बांस उत्पाद, कुटीर उद्योग तथा कृषि–आधारित प्रसंस्करण इकाइयाँ प्रमुख रूप से कार्यरत हैं। इन उद्योगों की खासियत यह है कि इनमें कम पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, जिससे स्थानीय उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने में सुविधा मिलती है। इसके अतिरिक्त, सरकार की विभिन्न योजनाएँ जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुद्रा योजना, इन उद्योगों के विकास में सहायक हैं। इन योजनाओं के माध्यम से युवाओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन मिलता है, जिससे वे आत्मनिर्भर बनते हैं। लघु उद्योग रोजगार सृजन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये श्रम–प्रधान होते हैं और स्थानीय मानव संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हैं। विशेषकर महिलाओं और युवाओं को इससे स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ बड़े उद्योगों की पहुँच सीमित होती है, वहाँ लघु उद्योग आजीविका का प्रमुख साधन बनते हैं और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में सहायक होते हैं। इन उद्योगों के सामने कई समस्याएँ भी हैं। पूंजी की कमी, आधुनिक तकनीक का अभाव, बाजार की अनिश्चितता तथा कच्चे माल की उपलब्धता जैसी चुनौतियाँ इनके विकास को प्रभावित करती हैं। इसके साथ ही, प्रशिक्षण और कौशल विकास की कमी के कारण श्रमिकों और उद्यमियों की उत्पादकता सीमित रहती है। बुनियादी सुविधाओं जैसे बिजली, सड़क और परिवहन की कमी भी एक बड़ी बाधा है। रायगढ़ जिले में लघु उद्योगों में रोजगार सृजन की व्यापक संभावनाएँ हैं, लेकिन इनके समुचित विकास के लिए वित्तीय सहायता को सरल बनाना, तकनीकी प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, बाजार सुविधाओं का विस्तार करना तथा आधारभूत ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है। यदि इन समस्याओं का समाधान किया जाए, तो लघु उद्योग क्षेत्रीय विकास और आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

मुख्य शब्द– लघु उद्योग, रोजगार सृजन, रायगढ़ जिला, कुटीर उद्योग, स्वरोजगार, आर्थिक विकास, समस्याएँ एवं चुनौतियाँ, उद्यमिता विकास, सरकारी योजनाएँ।

प्रस्तावना–

भारत एक विकासशील देश है, जहाँ आर्थिक विकास, सामाजिक उन्नति तथा रोजगार सृजन जैसे मुद्दे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। देश की विशाल जनसंख्या के कारण रोजगार की समस्या लंबे समय से एक गंभीर चुनौती रही है। इस संदर्भ में लघु, कुटीर एवं मध्यम उद्योगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये उद्योग न केवल उत्पादन और आय में वृद्धि करते हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन कर आर्थिक असमानताओं को कम करने में भी सहायक होते हैं। विशेषकर ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में, जहाँ बड़े उद्योगों की पहुँच सीमित होती है, वहाँ लघु उद्योग ही आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख आधार बनते हैं।

1.1 लघु उद्योग की अवधारणा–

लघु अथवा वृहद् की अवधारणा सापेक्षिक है। अमेरिका के जनरल मोटर्स के निवेश एवं फैलाव को देखते हुए भारत के बड़े–बड़े उद्योग भी बौने प्रतीत होते है। भारत में ही लौह–इस्पात एवं रेल्वे की तुलना में, रसायन एवं सीमेंट उद्योग छोटे प्रतीत होते हैं। फिर भी अध्ययन–अध्यापन की सुविधा एंव स्वतंत्र पहचान बनाये रखने के ध्येय से लघु उद्योगों को एकाधिक आधार पर परिभाषित करने का प्रयत्न सारे विश्व में किया गया है। परिभाषाओं की भी अपनी सीमा होती है। चीन के लघु उद्योग के संदर्भ में ड्वाईट पर्किन्स ने ठीक ही कहा है, "चीनी गणतंत्र में लघु–मान उद्योग में जैसी विवधिता पाई जाती है उसे संक्षिप्त वर्णन अथवा क्रमबद्ध लघु परिभाषा में व्यक्त कर न्याय नहीं किया जा सकता।"

"कुटीर उद्योग वे हैं जो पूर्णरूपेण अथवा प्रारंभिक रूप में परिवार क सदस्यों द्वारा पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक रोजगार के रूप में चलाए जाते हैं, जबकि लघु उद्योग वे हैं जो कि किराये के श्रमिकों द्वारा चलाए जाते हैं।

©Copyright 2025 *ADRJ*. All Rights Reserved

E ISSN -3048-8095 / Bimonthly / SJIF Impact- 5.16/ March - April 2026 / VOL-02 ISSUE-V

सामान्यतया यह श्रमिक 10 से 50 की सख्या के बीच होते हैं।" चीन में सहकारी कंपनियों में कार्यरत 50 से 600 व्यक्ति कृषि कार्यो को स्वदेशी संसाधनों एवं तकनीक का उपयोग करते हुए, सम्पादित करते हैं। 1960 में लघु उद्योग बोर्ड ने अपनी संस्कृति में कहा – "जहाँ पूंजीगत विनियोजन 5 लाख रूपये से अधिक न हो चाहे कितनी ही संख्या में श्रमिक कार्य करते हों।" इस व्याख्या से लघुता को व्यापकता मिल गई। यहाँ पूंजीगत विनियोग से आशय भूमि, भवन, मशीन एवं औजारों में निवेश से है। लघु उद्योग इकाई यदि किराये के भवन में चलाई जाती हों तो उसे 5 लाख रू. की सीमा में शामिल किया गया, किंतु श्रमिकों के आवास एवं अन्य श्रम कल्याण सुविधाओं को 5 लाख रू0 की परिधि से बाहर रखा गया।

लघु उद्योगों का वर्गीकरण तीन प्रकार उद्योगों में किया है–

1. सूक्ष्म उद्योग 2. लघु उद्योग 3. मध्यम उद्योग।

मुख्यतया लघु उद्योगों को इन में विनियोजित राशि के मापदण्डो से वर्गीकरण किया जाता है। निर्माण उपाय के अर्न्तगत सूक्ष्म उद्योग वह है जहाँ प्लाण्ट एवं मशीनरी में निवेश 25 लाख रूपये से अधिक नही होता है। लघु उद्योग वह है जहाँ प्लाण्ट एवं मशीनरी में निवेश 25 लाख रूपये से अधिक लेकिन 5 करोड़ रूपये से कम होता है। मध्यम उद्योग वह है जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में निवेश पॉच करोड़ रूपये से अधिक लेकिन 10 करोड़ रूपये से कम होता हो।सेवा उद्योग के स्वरूप में एक सूक्ष्म उद्योग वह है जहाँ उपकरणों में निवेश 10 लाख रूपये से आगे नहीं बढ़ता है और लघु उद्योग, जहाँ उपकरणों में निवेश 10 लाख रूपये से अधिक लेकिन 2 करोड़ रूपये से अधिक नही है एवं मध्यम उद्योग जहाँ उपकरणों में निवेश 2 करोड़ रूपये से अधिक लेकिन 5 करोड़ रूपये से कम न हो।भारतीय आर्थिक विकास में लघु एवं कुटीर पैमाने के उद्योगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। लघु पैमाने के उद्योग और कुटीर उद्योग भारत के विर्निमाण क्षेत्र की संरचना एवं स्वरूप के महत्वपूर्ण भाग है।

रायगढ़ जिले में लघु उद्योग–छत्तीसगढ़ राज्य का रायगढ़ जिला औद्योगिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो अपने समृद्ध खनिज संसाधनों, कृषि उत्पादों, वन संपदा तथा पारंपरिक कारीगरी के लिए जाना जाता है। यहाँ कोयला, लोहा और इस्पात उद्योगों की उपस्थिति के साथ–साथ अनेक लघु उद्योग भी विकसित हो रहे हैं। रायगढ़ की भौगोलिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ लघु उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल हैं, जिससे यह क्षेत्र रोजगार सृजन की अपार संभावनाएँ रखता है।

रायगढ़ जिले में लघु उद्योगों का स्वरूप विविधतापूर्ण है। यहाँ चावल मिल, धान प्रसंस्करण इकाइयाँ, बांस एवं लकड़ी आधारित उद्योग, हस्तशिल्प, लघु धातु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ तथा कुटीर उद्योग प्रमुख रूप से कार्यरत हैं। इन उद्योगों की विशेषता यह है कि ये स्थानीय संसाधनों पर आधारित होते हैं और कम पूंजी में स्थापित किए जा सकते हैं। इस कारण ये स्थानीय उद्यमियों, विशेषकर युवाओं और महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। रोजगार सृजन के संदर्भ में लघु उद्योगों का महत्व अत्यंत व्यापक है। ये उद्योग श्रम–प्रधान होते हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को कार्य के अवसर मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ कृषि पर अत्यधिक निर्भरता होती है, वहाँ लघु उद्योग कृषि के अतिरिक्त आय के स्रोत प्रदान करते हैं और लोगों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाते हैं। इसके अतिरिक्त, ये उद्योग क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने, पलायन को रोकने तथा स्थानीय स्तर पर विकास को प्रोत्साहित करने में भी सहायक होते हैं।

तकनीकी पिछड़ापन भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। कई लघु उद्योग आज भी पारंपरिक तकनीकों पर निर्भर हैं, जिससे उनकी उत्पादकता और गुणवत्ता प्रभावित होती है। आधुनिक मशीनों और तकनीकों का अभाव उन्हें बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में कमजोर बनाता है। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण और कौशल विकास की कमी के कारण श्रमिकों और उद्यमियों की दक्षता सीमित रहती है। बाजार संबंधी समस्याएँ भी लघु उद्योगों के विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। उत्पादों के विपणन के लिए उचित व्यवस्था का अभाव, ब्रांडिंग और पैकेजिंग की कमी, तथा बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा के कारण इन उद्योगों को अपने उत्पादों के लिए उचित मूल्य नहीं मिल पाता। कच्चे माल की अनियमित उपलब्धता और उसकी कीमतों में उतार–चढ़ाव भी उत्पादन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। बुनियादी ढांचे की कमी जैसे बिजली, सड़क, परिवहन, संचार सुविधाओं का अभाव भी लघु उद्योगों के विकास में एक बड़ी चुनौती है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में इन सुविधाओं की कमी के कारण उद्योगों का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो पाता। प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जटिलता और जानकारी के अभाव के कारण भी कई संभावित उद्यमी इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते।

अध्ययन का उद्देश्य

(1) रायगढ़ जिले के औद्योगिक परिदृश्य में लघु उद्योगों की स्थिति का पता लगाना ।

(2) लघु उद्योगों द्वारा दिये जाने वाले रोजगार उत्पादन की वर्तमान स्थिति एवं भावी संभावनाओं का पता लगाना ।

©Copyright 2025 *ADRJ*. All Rights Reserved

Akshardhara Research Journal
Single Blind Peer-Reviewed & Refereed International Research Journal
E ISSN -3048-8095 / Bimonthly / SJIF Impact- 5.16/ March - April 2026 / VOL-02 ISSUE-V

(3) लघुउद्योगों के स्थापना एवं संचालन में आने वाली समस्याओं का पता लगाना एवं उसके निराकरण हेतु उपाय प्रस्तुत करना।

परिकल्पना :–

1. लघु स्तरीय उद्योगों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है।
2. लघु स्तरीय उद्योगों को विपणन की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है।

शोध विधि –

इस शोध में ग्रामीणों की आर्थिक उन्नति के संदर्भ में लघु उद्योगों की समस्याओं, उनके समाधान तथा उनसे जुड़ी चुनौतियों का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त अनुसंधान पद्धति का चयन किया गया है। शोधकर्ता ने यह माना है कि किसी भी अध्ययन की सफलता उसके उद्देश्यों और समस्या की प्रकृति के अनुसार सही विधि के चयन पर निर्भर करती है। इसी दृष्टिकोण से प्रस्तुत लघुशोध में सर्वेक्षण विधि को अपनाया गया है। सर्वेक्षण विधि का तात्पर्य है कि किसी निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न स्थानों का प्रत्यक्ष अवलोकन करते हुए, संबंधित व्यक्तियों से संपर्क स्थापित कर आवश्यक जानकारी एकत्रित की जाए। इस प्रक्रिया में शोधकर्ता क्षेत्र में जाकर वास्तविक स्थिति का अध्ययन करता है, जिससे तथ्य अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय बनते हैं।

अध्ययन के लिए न्यादर्श के रूप में रायगढ़ जिले का चयन किया गया है। इस जिले में कार्यरत लघु उद्योगों से जुड़े व्यवसायियों को अध्ययन का आधार बनाया गया है। न्यादर्श चयन के लिए "स्तरीय दैव निदर्शन पद्धति" का उपयोग किया गया, जिसके अंतर्गत विभिन्न वर्गों से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए कुल 20 लघु उद्योग व्यवसायियों का चयन किया गया। इस पद्धति के माध्यम से संकलित आंकड़ों के आधार पर लघु उद्योगों की वास्तविक समस्याओं और चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है।

शोध में आंकड़ों के संकलन के लिए प्रश्नावली को मुख्य उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इस प्रश्नावली को इस प्रकार तैयार किया गया है कि लघु उद्योगों से संबंधित प्रमुख समस्याओं को व्यवस्थित रूप से समझा जा सके। इसके अंतर्गत समस्याओं को सात प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें कुशल श्रमिकों की कमी, उद्योग संचालन से जुड़ी समस्याएँ, वित्तीय कठिनाइयाँ, कच्चे माल की उपलब्धता से संबंधित समस्याएँ, आयात–निर्यात की बाधाएँ, वैधानिक (कानूनी) जटिलताएँ तथा उत्पादन संबंधी समस्याएँ शामिल हैं। इन सभी पहलुओं का समग्र अध्ययन करके लघु उद्योगों की वर्तमान स्थिति और उनके समक्ष उपस्थित चुनौतियों का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

4.1प्रश्नावली के आधार पर आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण :–

लघु उद्योग में आने वाली विभिन्न की समस्याओं को प्रश्नावली के माध्यम से विश्लेषण किया गया है इसके पश्चात् लघुउद्योग के व्यावसायिकों की समस्या का आंकलन किया गया है।

लघु उद्योगों में श्रमिकों की समस्या :–हमारे द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार अधिकतर लघु उद्योगों में श्रमिकों की समस्याऍ आती ही है। राजनांदगांव एक ऐसा क्षेत्र है जहां श्रमिक तो मिल जाते है परंतु कुशल श्रमिक आसानी से नहीं मिल पाते है कुशल श्रमिकों के अभाव के कारण उत्पादन क्षमता में गिरावट भी आती है। हमने 20 लघु उद्योगों के मालिकों से मिलकर यह आंकड़े एकत्रित किये है। जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है–

प्र.1 क्या राजनांदगाव में कुशल श्रमिकों का अभाव है?

तालिका क्र. 4.1

क्र.	विचार	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत में
1.	हॉ	15	75 %
2.	नहीं	5	25 %
	कुल	20	100%

विश्लेषण एवं व्याख्या :– उपरोक्त तालिका क्र. 4.1 में दर्शाये गये मान के अनुसार 75 प्रतिशत लघु उद्योग मालिकों ने कुशल श्रमिकों के आभाव में विचार व्यक्त किया है, तथा 25 प्रतिशत लघु उद्योग के मालिक का विचार कुशल श्रमिकों का आभाव नहीं है। जिससे स्पष्ट होता है कि राजनांदगांव जिले के लघु उद्योगों में कुशल श्रमिकों का आभाव अधिक होता है। कुछ ही लघु उद्योग में कुशल श्रमिकों का आभाव नहीं होता है।

प्र.2 क्या श्रमिक पलायन कर जाते है? हां तो क्यों?

तालिका क्र. 4.2

क्र.	विचार	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत में
1.	हॉ	9	45 %
2.	नहीं	11	55 %
	कुल	20	100%

©Copyright 2025 *ADRJ*. All Rights Reserved

Akshardhara Research Journal
Single Blind Peer-Reviewed & Refereed International Research Journal
E ISSN -3048-8095 / Bimonthly / SJIF Impact- 5.16/ March - April 2026 / VOL-02 ISSUE-V

विश्लेषण एवं व्याख्या :–उपरोक्त तालिका क्र. 4.2 में दर्शाये गये मान के अनुसार 20 में से 9 (45 प्रतिशत) लघु उद्योगों की उचित परिश्रमिक समस्या यह है, तथा 11 (55 प्रतिशत) लघु उद्योगों में श्रमिकों को उचित परिश्रमिक मिलती है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि अधिकतर लघु उद्योगों श्रमिकों को उचित परिश्रमिक नहीं मिलने के कारण श्रमिक पलायन कर जाते है।

लघु उद्योग में वित्तीय समस्या :–

प्र.3 उद्योग हेतु आवश्यक राशि उपलब्ध होती है?

तालिका क्र. 4.3

क्र.	विचार	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत में
1.	हॉ	16	80 %
2.	नहीं	4	20%
	कुल	20	100%

विश्लेषण एवं व्याख्या :– उपरोक्त तालिका क्र. 4.3 में दर्शाये गये मान के अनुसार 20 उत्तरदाताओं में से 16 (80 प्रतिशत) लघु उद्योगों को अपने व्यवसाय को स्थापित करने के लिए पर्याप्त राशि की आवश्यकता उपलब्ध होती है, तथा 20 उत्तरदाताओं में से 4 (20 प्रतिशत) लघु उद्योगों के लिए आवश्यक राशि की आवश्यकता होती है।

प्र.4 क्या बैकों से ऋण हेतु पर्याप्त राशि प्राप्त हो जाती है?

तालिका क्र. 4.4

क्र.	विचार	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत में
1.	हॉ	16	80 %
2.	नहीं	4	20%
	कुल	20	100%

विश्लेषण एवं व्याख्या :– उपरोक्त तालिका क्र. 4.4 में दर्शाये गये मान के अनुसार 20 उत्तरदाताओं में से 16 (80 प्रतिशत) लघु उद्योगों को अपने व्यवसाय को स्थापित करने के लिए बैंको से ऋण हेतु पर्याप्त राशि प्राप्त हो जाती है, तथा 20 उत्तरदाताओं में से 4 (20 प्रतिशत) लघु उद्योगों के लिए आवश्यक राशि की उपलब्ध नहीं होती है।

प्र.5 क्या उपयोग हेतु सरकारी अनुदान की राशि प्राप्त होती है?

तालिका क्र. 4.5

क्र.	विचार	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत में
1.	हॉ	11	55 %
2.	नहीं	9	45%
	कुल	20	100%

विश्लेषण एवं व्याख्या :– उपरोक्त तालिका क्र. 4.5 में दर्शाये गये मान के अनुसार 20 उत्तरदाताओं में से 11 (55 प्रतिशत) लघु उद्योग व्यवसायियों को लघु उद्योग के उपयोग हेतु सरकारी अनुदान की राशि प्राप्त होती है। तथा 20 उत्तरदाताओं में से 9 (45 प्रतिशत) लघु उद्योगों के लिए राशि लघु उद्योग के लिए सरकारी अनुदान की राशि प्राप्त नहीं होती है। कुछ उद्योगों को सरकारी अनुदान की राशि प्राप्त होती हैं एवं कुछ उद्योगों को अनुदान राशी नही मिलती हैं यह सरकारी नियम के अनुसार दिया जाता हैं।

लघु उद्योग में कच्चे माल की समस्या :–

प्र.6 कच्चे माल की आपूर्ति समय पर हो जाती है? यदि नही हुई तो उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है?

तालिका क्र. 4.6

क्र.	विचार	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत में
1.	हॉ	10	50 %
2.	नहीं	10	50 %
	कुल	20	100%

विश्लेषण एवं व्याख्या :– उपरोक्त तालिका क्र. 4.6 में दर्शाये गये मान के अनुसार 20 उत्तरदाताओं में से 10 (50 प्रतिशत) लघु उद्योग के मालिकों को कहना है कि कच्चे माल की आपूर्ति समय पर नहीं होती है। तथा 10 (50 प्रतिशत) उद्योगों में कच्चे माल की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। क्योंकि इनके उद्योगों के लिए कच्चे माल

©Copyright 2025 *ADRJ*. All Rights Reserved

Akshardhara Research Journal
Single Blind Peer-Reviewed & Refereed International Research Journal
E ISSN -3048-8095 / Bimonthly / SJIF Impact- 5.16/ March - April 2026 / VOL-02 ISSUE-V

ज्यादातर आसानी से बाजारों में मिल जाती है। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कच्चे माल की समस्या उनके सामग्री के उत्पादन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है।

प्र.7 क्या स्थानीय क्षेत्रों से कच्चे माल की प्राप्ति हो पाती है?

तालिका क्र. 4.7

क्र.	विचार	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत में
1.	हॉ	16	55 %
2.	नहीं	4	45%
	कुल	20	100%

विश्लेषण एवं व्याख्या :– उपरोक्त तालिका क्र. 4.7 में दर्शाये गये मान के अनुसार 20 उत्तरदाताओं में से 8 (40 प्रतिशत) लघु उद्योग के मालिकों को कहना है कि स्थानिय क्षेत्रों में कच्चे माल की प्राप्ति हो जाती है। तथा 12 (60 प्रतिशत) उद्योगों में स्थानिय क्षेत्रों से कच्चे की प्राप्ति नहीं हो पाती है। क्योंकि इनके उद्योगों के लिए कच्चे माल ज्यादातर आसानी से बाजारों में नहीं मिलते है। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कच्चे माल की समस्या उनके सामग्री के उत्पादन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। कच्चा माल व्यवसाय के उत्पादन कार्य हेतु अत्यंत आवश्यक हैं।

लघु उद्योग में वितरण की समस्या :–

प्र. 8 क्या परिवेश समस्या में वितरण में बाधा उत्पन्न होती है?

तालिका क्र. 4.8

क्र.	विचार	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत में
1.	हॉ	15	75 %
2.	नहीं	5	25%
	कुल	20	100%

विश्लेषण एवं व्याख्या :–उपरोक्त तालिका क्र. 4.8 में दर्शाये गये मान के अनुसार 20 में से 15 (75 प्रतिशत) लघु उद्योग के मालिकों को कहना है कि लघुउद्योग के परिवेश (गली–मोहल्ला) में समान के वितरण में बाधा उत्पन्न होती है। क्योंकि अधिकतर छोटे लघुउद्योग शहर के अंदर होता है। और शेष 5 (25 प्रतिशत) लघु उद्योगों के मालिकों का कहना है कि इस प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है।

प्र. 9 वितरण माध्यम कैसे है? (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष)

तालिका क्र. 4.9

क्र.	विचार	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत में
1.	प्रत्यक्ष	10	50 %
2.	अप्रत्यक्ष	10	50%
	कुल	20	100%

विश्लेषण एवं व्याख्या :– उपरोक्त तालिका क्र. 4.9 में दर्शाये गये मान के अनुसार 20 उत्तरदाताओं में से 10 (75 प्रतिशत) लघु उद्योग के मालिकों को कहना है कि वह प्रत्यक्ष वितरण प्रणाली के माध्यम से समान का वितरण करते है। और 10 (50 प्रतिशत) लघु उद्योगों के मालिकों का कहना है कि अप्रत्यक्ष वितरण प्रणाली के माध्यम से समान का वितरण करते है।

परिकल्पना हेतु आंकड़ों से प्राप्त निष्कर्ष :–

परिकल्पना क्रमांक –1

1. लघु स्तरीय उद्योगों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है।

निष्कर्ष :– राजनांदगांव के लघु उद्योगों में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि राजनांदगांव जिले के अधिकतर लघु उद्योगों में कुशल श्रमिक, वित्तीय समस्या, परिवहन समस्या, कच्चे माल की समस्या, उत्पादन की समस्या आदि विभिन्न प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हमारी परिकल्पना क्र.–1 लघु स्तरीय उद्योगों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। परिकल्पना 1 अस्वीकृत होती है।

परिकल्पना क्रमांक –2

2. लघु स्तरीय उद्योगों को विपणन की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है।

निष्कर्ष :– राजनांदगांव के लघु उद्योगों में विपणन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि राजनांदगांव जिले के अधिकतर लघु उद्योगों में विपणन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि लघु

©Copyright 2025 *ADRJ*. All Rights Reserved

Akshardhara Research Journal
Single Blind Peer-Reviewed & Refereed International Research Journal
E ISSN -3048-8095 / Bimonthly / SJIF Impact- 5.16/ March - April 2026 / VOL-02 ISSUE-V

उद्योगों में विपणन अहम भूमिका निभाता है। सभी कार्य विपणन पर निर्भर करता है। जैसे कच्चे माल का क्रय, बिजली बिल, श्रमिकों को वेतन आदि विभिन्न प्रकार की विपणन पर निर्भर करता है। इसलिए हमारी परिकल्पना क्र.–2 लघु स्तरीय उद्योगों को विपणन की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। परिकल्पना 2 अस्वीकृत होती है।

सुझाव :–

1. लघु उद्योग के बारे में गांव–गांव जाकर जागरूकता फैलानी चाहिए। जिससे शहरी लोंगों के साथ–साथ ग्रामीणों में इसकी जानकारी होनी चाहिए।
2. किसी भी लघु उद्योग के लिए संतुलित विकास की नीति को अपनाना चाहिए।
3. कृषि क्षेत्रों के लिए वित्तीय साधन उपलब्ध कराना चाहिए।
4. लघु उद्योगों के निर्माण के लिए ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए।
5. लघु उद्योग हेतु ऋण स्वीकृति तथा वितरण को त्वरित करना चाहिए।
6. समय समय पर वित्तीय कार्ययोजनाका निरीक्षण करना चाहिए।
7. नवीन लघु उद्योग स्थापित करने वाली इकाई को ऋण प्रदान करने प्राथमिकता देनी चाहिए।
8. लघु उद्योग में वेतन को अच्छी होनी चाहिए।
9. लघु उद्योग हेतु बैंक द्वारा दिये गये ऋण का ब्याज कम होनी चाहिए।

उपसंहार–

प्रस्तुत अध्ययन के विश्लेषण एवं व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि लघु उद्योग, विशेषकर राजनांदगांव (और इसी संदर्भ में रायगढ़ जैसे औद्योगिक क्षेत्रों) में, रोजगार सृजन के महत्वपूर्ण साधन होने के बावजूद अनेक समस्याओं और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह पाया गया कि लघु उद्योगों में वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के माध्यमों का उपयोग किया जाता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विपणन व्यवस्था इनके संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परिकल्पनाओं के परीक्षण से यह सिद्ध हुआ कि लघु उद्योगों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुशल श्रमिकों की कमी, वित्तीय संसाधनों का अभाव, परिवहन संबंधी कठिनाइयाँ, कच्चे माल की अनियमित उपलब्धता तथा उत्पादन से जुड़ी बाधाएँ इनके विकास में प्रमुख अवरोध हैं। इसी प्रकार, विपणन से संबंधित समस्याएँ भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उत्पादों की बिक्री, लागत की वसूली तथा लाभ अर्जन पूरी तरह से विपणन तंत्र पर निर्भर करता है। इस कारण दोनों परिकल्पनाएँ अस्वीकृत सिद्ध हुईं, जो यह दर्शाती हैं कि लघु उद्योगों के समक्ष वास्तविक समस्याएँ व्यापक और जटिल हैं। अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि लघु उद्योगों में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएँ निहित हैं। ये उद्योग स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर ग्रामीण एवं अर्ध–शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करते हैं तथा आर्थिक विकास को गति देते हैं। विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के लिए ये उद्योग आत्मनिर्भरता का माध्यम बन सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. शर्मा, आर. (2018). लघु उद्योग और ग्रामीण विकास. नई दिल्ली : राज पब्लिकेशन।
2. गुप्ता, पी. (2017). भारत में लघु उद्योगों की समस्याएँ. नई दिल्ली : दीप एंड दीप पब्लिकेशन।
3. कुमार, एस. (2020). अनुसंधान पद्धति. दिल्ली : पियरसन एजुकेशन।
4. सिंह, ए. (2019). एमएसएमई और रोजगार सृजन की भूमिका. जयपुर : आरबीएसए पब्लिशर्स।
5. मिश्रा, के. (2016). भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योगों का महत्व. वाराणसी : विश्व भारती प्रकाशन।
6. भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय(2022). वार्षिक रिपोर्ट. नई दिल्ली।
7. छत्तीसगढ़ शासन (2021). औद्योगिक नीति एवं कार्य योजना. रायपुर : उद्योग विभाग।
8. नाबार्ड (छ।ठ।त्क) (2020). ग्रामीण विकास रिपोर्ट. मुंबई।
9. दत्त, आर. एवं सुंदरम, के.पी.एम. (2019). भारतीय अर्थव्यवस्था. नई दिल्ली : एस. चंद एंड कंपनी।
10. चौधरी, वी. (2015). उद्यमिता विकास और लघु उद्योग प्रबंधन. जयपुर : हिमालय पब्लिशिंग हाउस।